(2008)11 एस.सी.आर. 66

राज राजेंद्र सिंह सेठ@आर.आर.एस. सेठ

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1135/2008)

जुलाई 22, 2008

(डॉ अरिजीत पसायत, एस.एच. कपाड़िया, जे.जे.)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947: धारा 5 (1)(घ) के साथ पठित धारा 5 (2)- दोषसिद्धि- इस आधार पर कि डॉक्टर ने उचित चिकित्सा उपचार देने के लिए रिश्वत मांगी-का औचित्य- अभिनिर्धारित न्यायोचित-साक्ष्य यह स्थापित करता है कि डॉक्टर ने वार्ड बॉय को पैसे देने के लिए कहा जिसने बदले में उन्हें सौंप दिया- रिश्वत की मांग और स्वीकृति को साबित करने वाली सभी आवश्यकताएँ स्थापित -दंड संहिता, 1860 - धाराएँ 120बी और 161.

अभियोजन का मामला यह था कि शिकायतकर्ता पीडब्लू-3 के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ अपीलार्थी डॉक्टर था और आरोपी संख्या 2 वार्ड बॉय था। पीडब्लू-3 के पिता ने उसे उचित चिकित्सा की कमी के बारे में शिकायत की। पीडब्लू-3 ने आरोपी संख्या 2 से निवेदन किया कि अपीलर्थी से मिलने के लिए अनुमत करे। पीडब्लू-3 ने अपीलर्थी से मुलाक़ात की जिसने उसके पिता को उचित इलाज करने के लिए 500 रुपए मांगें और इस राशि का 1.9.1985 को भुगतान करने पर भी जोर दिया। डॉक्टर ने पीडब्लू-3 को यह भी बताया कि अगर वह अस्पताल में

उपलब्ध नहीं है, तो वह उसके वार्ड बॉय को राशि का भुगतान करेगा, जो यह राशि उसे दे देगा।

पीडब्लू-3 ने शिकायत दर्ज कराई। जाल बिछाया गया और रिश्वत के पैसे का भुगतान करने के लिए तय दिन, अपीलार्थी और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी और अभियुक्त को आई.पी.सी. की धाराओं 120 बी और 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1)(घ) के साथ पठित धारा 5 (2) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया। उनमें से प्रत्येक को एक वर्ष के लिए कठोर दंड और जुर्माना देने की सजा सुनाई गई थी।

अपील पर, उच्च न्यायालय ने कहा की आरोप स्थापित होते हैं लेकिन समय के अंतराल को देखते हुए सजा भुगती हुई सजा की अवधि तक कम कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1. साक्ष्य इस प्रकार है की अपीलर्थी ने पीडब्लू-3 से सह-अभियुक्त को पैसे देने के लिए कहा था, जो उसे पैसे पहुंचा देता। पीडब्लू-2 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह निर्णय सी.बी.आई. कार्यालय में लिया गया था कि आरोपी सं-2 को पैसे का भुगतान करना है जिसने अभियुक्त को भुगतान कर दिया। इसी तरह, पीडब्लू-10 पीडब्लू-3 द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच करते हुए यह कथन किया है कि वह अपीलार्थी के निवास पर गया और उसने खुद को झाड़ी के पीछे छिपा लिया और वहाँ से उन्होंने पीडब्लू-3 और अपीलार्थी के बीच बातचीत सुनी। उसने कहा है कि अपीलार्थी ने पीडब्लू-3 को आरोपी नं. 2 को भुगतान करने को कहा। पीडब्लू-3 ने पीडब्लू-10 जो एक सिपाही है के बयान के इस हिस्से की पुष्टि की।

उसे पीडब्लू-3 द्वारा लगाए गए आरोपों की वास्तविकता को सत्यापित करने का काम के दिया गया था। वह उसके कक्ष में गया और अभियुक्त सं 2 वहाँ उपस्थित था। पीडब्लू 1 और 2 स्वतंत्र गवाह है और उनकी उपस्थिती में अभियुक्त सं 2 को पीडब्लू 3 द्वारा पैसे का भुगतान किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब पीडब्लू-3 और अन्य अस्पताल पहुंचे तो चैंबर बंद पाया गया। पीडब्लू-3 अभियुक्त सं 2 से मिला और उसे पैसे का भुगतान किया और अपीलर्थी के घर चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद पीडब्लू-3 और अभियुक्त सं 2 गेट के अंदर चले गए और पीडब्लू-2 और अन्य गेट पर बने रहे। साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी कॉल की घंटी दबाने के बाद सामने आया और अभियुक्त सं 2 ने उसे पैसे दे दिये। पीडब्लू-2 जिन्होंने अपीलार्थी को पैसा देते हुए देखा, ने संकेत दिया और उसके तुरंत बाद अभियुक्त सं 2 और अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और अपीलार्थी के दाहिने हाथ से धन बरामद किया गया और अभियुक्त व्यक्तियों के दोनों हाथ अलग घोल में धोए गए थे और वे गुलाबी हो गए। मुद्रा नोट भी बरामद किए गए और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई। यह दलील कि अपीलार्थी द्वारा कोई मांग नहीं की गई है, अभिलेख पर साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से गलत साबित होती है। साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अपीलार्थी ने अभियुक्त सं 2 को पैसे देने के लिए कहे जिसने बाद में अपीलार्थी को पैसे सौंप दिए। रिश्वत की मांग और स्वीकृति को साबित करने के लिए सभी आवश्यकताएं स्थापित कर ली गई हैं। [पैरा 8,10] [72-सी, डी, ई, एफ, जी, एच; 73-ए एंड बी; 74-डी]

बी. नोहा बनाम केरल राज्य और अन्य (2006) 12 एससीसी 277 - पर भरोसा किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 1135/2008.

आपराधिक अपील सं. 7/1998 (आर) में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 10/9/2003 से।

अपीलार्थी के लिए सी. डी. सिंह और मेरुसागर सामंताराय।

प्रतिवादी सं 2 के लिए राजीव दत्ता, साकेत सिंह और पी. परमेस्वरन।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी गई है। वर्तमान अपीलकर्ता और आरोपी नंबर 2 नाग नारायण द्वारा दो अपीलें दायर की गई थीं, जिसमें आरसी मामला सं- 15/1998 में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, रांची द्वारा पारित 4 दिसंबर, 1997 के फैसले और 16.12.1997 की सजा के आदेश की सत्यता पर सवाल उठाया गया था। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में ' आईपीसी ') की धारा 120 बी और 161, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 5 (1) (घ) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 5(2) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया। उनमें से प्रत्येक को एक वर्ष के लिए कठोर कारावास से गुजरने और डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ 5,00/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

3. मुकदमे के दौरान सामने आया अभियोजन पक्ष का विवरण इस प्रकार है:

बीसीसीएल, धनबाद के पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी एरिया-9 के सफाई मजदूर राजू हादी ने 1.9.1985 को एसपी सीबीआई, धनबाद को एक लिखित शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह अपने पिता श्री हुबलाल हादी के इलाज के सिलसिले में चामोडीह डिस्पेंसरी गए थे जिनकी डॉक्टर एलबी साह ने जांच की, जिन्होंने उसे सेंट्रल हॉस्पिटल, धनबाद रेफर कर दिया। हुबलाल हादी को 29.8.1985 को

सेंट्रल अस्पताल के बेड नंबर 16 ईएनटी विभाग में भर्ती कराया गया था। राजू हादी 31.8.1985 को अपने बीमार पिता को देखने के लिए अस्पताल गए थे और उनके बीमार पिता ने उचित इलाज की कमी की शिकायत की और उन्होंने उनसे संबंधित डॉक्टर से मिलने का अनुरोध किया, राजू हादी को पता चला कि उनके पिता का इलाज डॉ. आरआरएस सेठ, अपीलकर्ता के अधीन था। उन्होंने नाग नारायण से उन्हें डॉ. आरआरएस सेठ से मिलने की अनुमति देने का अनुरोध किया और डॉ. आरआरएस सेठ से मुलाकात की, जिन्होंने उनके पिता को उचित चिकित्सा उपचार देने के लिए उनसे 500/- रुपये की राशि की मांग की और इस बात पर भी जोर दिया कि राशि 1.9.1985. को भुगतान की जाए। डॉक्टर ने राजू हादी से यह भी कहा कि यदि वह अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो तो, तो वह उसके वार्ड बॉय नाग नारायण को राशि का भुगतान करेगा, जो राशि उसको दे देगा। चूंकि राजू हादी डॉक्टर और वार्ड बॉय को रिश्वत की रकम देने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसपी सीबीआई, धनबाद को शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुष्टि रिपोर्ट मिलने पर सत्यापन किया गया और निरीक्षक श्री आरसी चौधरी ने 1.9.1985 को शिकायत दर्ज की और जांच शुरू की। आईओ ने दो स्वतंत्र गवाहों देवराज प्रसाद सिन्हा (पीडब्लू-2) और वेद प्रकाश पाहुजा (पीडब्लू-1) की सेवाएं प्राप्त कीं। इन दोनों स्वतंत्र गवाहों ने सी.बी.आई. के कार्यालय में श्री आर.सी. चौधरी के समक्ष रिपोर्ट की। इसके बाद सीबीआई के सदस्यों ने एक छापेमारी दल का गठन किया और यह दल भी उनके सामने इकट्ठा हुआ। एक-दूसरे के औपचारिक परिचय के बाद, बैठक का उद्देश्य समझाया गया और दो स्वतंत्र गवाहों और छापा मारने वाले दल के सदस्यों की तत्काल उपस्थिति में फिनोलफथेलिन पाउडर के उद्देश्य और उपयोग और सोडियम कार्बोनेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद, सूचना देने वाले राजू हादी

को 500/- रुपये (प्रत्येक एक सौ रुपये के पांच जीसीसी नोट) प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और उसने इसे प्रस्तुत किया और इन नोटों की संख्या नोट कर ली गई और इन जीसीसी नोटों पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगाकर राजू हादी को सौंप दिया गया। सूचक को निर्देश दिया गया था कि आरोपी को राशि मांगने पर ही भुगतान किया जाये। गवाहों और छापेमारी दल के सदस्यों को ट्रैप से पहले और बाद में अपनी-अपनी भूमिका निभाने का निर्देश भी जारी किया गया। इन सभी व्यावहारिक प्रदर्शनों को नोट कर लिया गया और प्रदर्शन चार्ट तैयार किया गया जिस पर छापा मारने वाले दल के सभी सदस्यों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

प्री-ट्रैप औपचारिकताओं के बाद, पीडब्लू 3 और स्वतंत्र गवाहों सहित टीम के अन्य सदस्य सेंट्रल अस्पताल की ओर बढ़े और पीडब्लू 2 को पीडब्लू 3 के नजदीक रहने और पीडब्लू 3 और अपीलकर्ताओं के बीच की बातचीत सुनने का निर्देश दिया गया। जब वे सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचे और अपीलकर्ता डॉ. सेठ के चैंबर में गए, तो चैंबर बंद पाया गया, लेकिन मुखबिर ने अन्य अपीलकर्ता नाग नारायण से मुलाकात की और पीडब्ल्यू 3 ने नाग नारायण को 500/- रुपये की रंग लगी राशि का भुगतान किया, जिसने उसे अपने उसकी शर्ट की दायीं जेब में रखा और पीडब्लू3 से कहा कि वह उसके साथ डॉ. सेठ के आवास पर चले क्योंकि वह उसकी उपस्थिति में पैसे देगा और पीडब्लू 3 अपीलकर्ता नाग नारायण सेंट्रल हॉस्पिटल से डॉ. सेठ के आवास की ओर बढ़े और पीडब्लू 2 और टीम के अन्य सदस्य उनके पीछे चल रहे थे। जब पीडब्लू3 गेट के पास रहा, तो टीम के अन्य व्यक्ति गेट के बाहर रहे। घर के बुरांद पहुंचने पर, अपीलकर्ता नाग नारायण ने कॉल बेल दबाई, जिस पर अपीलकर्ता डॉ. सेठ दरवाजा खोलकर बाहर आए और उसने उन्हें पैसे दिए। इस बीच, पीडब्ल्यू 2 जिसने यह देखा, गेट से बाहर आया और संकेत दिया और उसके बाद टीम के सदस्यों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए उन पर धावा बोल दिया और और उन्होंने डॉ. सेठ को पकड़ लिया और

उनके कब्जे से पैसे बरामद कर लिए, नाग नारायण को भी पकड़ लिया गया। इसके बाद डॉ. सेठ के दाहिने हाथ को एक घोल में डुबाया गया जो गुलाबी हो गया और इस घोल को एक बोतल में रखकर सील कर दिया गया। इसी प्रकार डॉ. सेठ का बायां हाथ भी दूसरे घोल में डुबाया गया, वह भी गुलाबी हो गया और इस घोल को भी एक अलग बोतल में रखकर सील कर दिया गया। उसी समय, अपीलकर्ता नाग नारायण के दाहिने हाथ को भी इसी तरह के घोल में डुबोया गया, जो गुलाबी हो गया और उसे एक बोतल में रखकर सील कर दिया गया। इसी प्रकार नाग नारायण के बाएँ हाथ को भी दूसरे घोल में डुबाया गया, वह भी गुलाबी हो गया और इस घोल को भी एक बोतल में रखकर सील कर दिया गया। उनकी शर्ट को भी एक घोल में डुबोया गया और वह घोल गुलाबी हो गया और उस घोल को एक बोतल में रखकर सील कर दिया गया। इसके बाद टीम के सदस्यों ने सीलबंद सभी बोतलों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद डॉ. सेठ के परिसर में पोस्ट-ट्रैप औपचारिकताएं पूरी की गईं, जिस पर टीम के सभी सदस्यों ने अपने- अपने हस्ताक्षर किए। बाद में पैसे की बरामदगी के तुरंत बाद नाग नारायण और डॉ. सेठ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच के बाद मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और मामले का संज्ञान लिया गया और निचली अदालत ने मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए और दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों के प्रदर्श चिह्नित किए और अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचे और दोनों अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया और तदनुसार, उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

4. दोनों आरोपी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उनका कहना था कि गवाहों की गवाही में काफी विरोधाभास है। यह प्रस्तुत किया गया कि सब कुछ पूर्व नियोजित था और अपीलकर्ता को झूठा फंसाने की साजिश रची गई थी। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ट्रैप से पहले इतनी तैयारी की गई थी, लेकिन यह

स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ता के हाथ से पैसा किसने बरामद किया। यह कहा गया था कि तथाकथित जाल के पीछे पीडब्लू8 का दिमाग था।

5. प्रतिद्वंदीयों के रुख पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने माना कि आरोप स्थापित हो गए थे, लेकिन समय बीतने पर विचार करते हुए सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक कम कर दिया गया।

6. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया:

(1) कोई मांग स्थापित नहीं की गई;

(2) पीडब्लू-8 की भूमिका अत्यधिक संदिग्ध है और उसके साक्ष्यों में अभाव है

(3) कोई स्वतंत्र गवाह नहीं थे;

(4) इस बात का कोई सकारात्मक सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता से अभियोजन पक्ष के दावे के अनुसार, पैसे किसने वसूले थे।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने साक्ष्यों का विस्तार से विश्लेषण किया है और आक्षेपित निर्णय में कोई खामी नहीं है।

8. इस तथ्य को लेकर काफी चर्चा हुई है कि ज्यादातर गवाह एक ही कार्यालय में थे। सबूत इस बात का है कि अपीलकर्ता ने पीडब्लू-3 से सह-अभियुक्त नाग नारायण को पैसे देने के लिए कहा था, जो उसे पैसे दे देता। पीडब्लू-2 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि सीबीआई कार्यालय में निर्णय लिया गया था कि पैसा नाग नारायण को दिया जाएगा जिसने आरोपी को भुगतान किया है। इसी प्रकार, पीडब्लू-10 ने पीडब्लू-3 द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता के बारे में सत्यापन करते हुए कहा है कि वह अपीलकर्ता के आवास पर गया और उसने खुद को झाड़ी के पीछे छिपा लिया और

वहां से उसने पीडब्लू-3 और अपीलकर्ता के बीच की बातचीत सुनी। उन्होंने कहा है कि अपीलकर्ता ने पीडब्लू-3 से नाग नारायण को भुगतान करने के लिए कहा। पीडब्लू-3 ने पीडब्लू-10 जो एक कांस्टेबल है, के बयान के इस हिस्से की पुष्टि की। उन्हें पीडब्लू-3 द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता को सत्यापित करने का काम सौंपा गया था। वह अपने चैंबर में गए और नाग नारायण वहां मौजूद थे। पीडब्लू 1 और 2 स्वतंत्र गवाह थे और उनकी उपस्थिति में पीडब्लू-3 द्वारा नाग नारायण को पैसा दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब पीडब्लू-3 और अन्य लोग अस्पताल पहुंचे तो चैंबर बंद पाया गया। पीडब्लू-3 ने नाग नारायण से मुलाकात की और उन्हें पैसे दिए और अपीलकर्ता के निवास पर चले गए। वहां पहुंचने के बाद पीडब्लू-3 और नाग नारायण गेट के अंदर चले गए और पीडब्लू-2 और अन्य गेट पर ही रह गए। सबूतों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता कॉल बेल बजने के बाद बाहर आया और नाग नारायण ने उसे पैसे दिए। पीडब्लू-2, जिसने अपीलकर्ता को पैसे देते हुए देखा, ने एक संकेत दिया और उसके तुरंत बाद नाग नारायण और अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और अपीलकर्ता के दाहिने हाथ से पैसे बरामद कर लिए गए और आरोपी व्यक्तियों के दोनों हाथों को अलग-अलग घोल में धोया गया और वे गुलाबी हो गए। करेंसी नोट भी बरामद कर लिए गए और आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किया गया। यह दलील कि अपीलकर्ता द्वारा कोई मांग नहीं की गई है, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से झुठला दी गई है। सबूत स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अपीलकर्ता ने नाग नारायण को पैसा देने के लिए कहा था, जिसने बदले में पैसा अपीलकर्ता को सौंप दिया।

9. बी. नोहा बनाम केरल राज्य और अन्य (2006 (12) एससीसी277) में अन्य बातों के साथ-साथ, इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार देखा गया:

> "10. साक्ष्य से पता चलता है कि जब पीडब्लू-1 ने आरोपी को बताया कि वह आरोपी के निर्देशानुसार पैसे लाया है, तो आरोपी ने

पीडब्लू-1 से कहा हिस्सा रख लो और उसे वह दे दो। जब यह साबित हो जाता है कि पैसे की स्वैच्छिक और सचेत स्वीकृति थी, तो मांग या मकसद को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर कोई अतिरिक्त बोझ डालने की जरूरत नहीं है। इसका निष्कर्ष विशेष मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियाँ से निकाला जाना है।

मधुकर भास्करराव जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2000 (8) एससीसी 571) में इस न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था:

"12. अनुमान लगाने के लिए तथ्यों पर स्थापित किया जाने वाला आधार यह है कि परितोषण का भुगतान या स्वीकृति थी। एक बार जब उक्त आधार स्थापित हो जाता है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त परितोषण को 'मकसद या इनाम के रूप में' स्वीकार किया गया था कोई आधिकारिक कार्य करने या न करने के लिए। इसलिए 'परितोषण' शब्द को इनाम के अर्थ में विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनाम उस प्रकल्पना का परिणाम है जिसे अदालत को तथ्यात्मक आधार पर निकालना होता है कि 'परितोषण' का भुगतान किया गया था।

'परितोषण या कोई मूल्यवान वस्तु' जैसी एक-दूसरे से सटे दो अभिव्यक्तियों की स्थिति को देखकर यह फिर से मजबूत हो जाएगा। यदि किसी मूल्यवान वस्तु को स्वीकार करने से यह प्रकल्पना करने में मदद मिल सकती है कि इसे किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के मकसद या इनाम के रूप में स्वीकार किया गया था, तो 'परितोषण' शब्द को इस संदर्भ में, उस लोक सेवक को संतुष्टि देने के

लिए किसी भी भुगतान के अर्थ में माना जाना चाहिए जिसने इसे प्राप्त किया।

11. एम. नरसिंगा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2001 (1) एससीसी 691) में इस न्यायालय द्वारा इस निर्णय का पालन किया गया। अभियुक्त का ऐसा कोई मामला नहीं है कि उक्त राशि उसे उस राशि के रूप में प्राप्त हुई थी जिसे वह पीडब्लू-1 से प्राप्त करने या लेने का कानूनी रूप से हकदार था। आंध्र प्रदेश राज्य बनाम कोम्माराजू गोपाल कृष्ण मूर्ति (2000 (9) एससीसी 752) के फैसले में यह माना गया था कि जब यह पाया जाता है कि राशि लोक सेवक को हस्तांतरित कर दी गई है तो यह स्थापित करने की ज़िम्मेदारी लोक सेवक पर है कि ऐसा अवैध परितोषण के माध्यम से नहीं किया गया था। अभियुक्त द्वारा उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया।"

10. वर्तमान मामले में रिश्वत की मांग और स्वीकृति को साबित करने के लिए सभी आवश्यक शर्तें स्थापित कर ली गई हैं।

11. इसलिए, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

डी जी

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।